काका जॉगिन्दर सिंह आलिया धर्ती पाकड़

वी.

के. आर. नारायणन भारत के उपराष्ट्रपति

16 जुलाई, 1993

[जे. एस. वर्मा, के. जयचंद्र रेड्डी,

योगेश्वर दिवस, जी. एन. राय और एस. पी. भरुचा, जे. जे.]

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952-धारा 18 (1)-अनुचित प्रभाव-आधार-आवश्यक तत्व-अभिवचनों में कमी-का प्रभाव।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952-धारा एस. बी.-उद्देश्य और आवश्यकता-नामांकन पत्र-अस्वीकृति-कब

दोष महत्वपूर्ण नहीं हैं-का प्रभाव।

चुनाव-उप-राष्ट्रपति चुनाव-अनुचित प्रभाव का आधार-दलीलों में दक्षता की कमी-नामांकन पत्र में दोष पर्याप्त नहीं हैं। प्रकृति-का प्रभाव।

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

जांच के समय, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा दायर नामांकन पत्रों की वैधता पर आपत्ति जताई। निर्वाचन अधिकारी

आपत्तियों को खारिज कर दिया और दोनों के नामांकन पत्रों को वैध पाया। आयोजित मतदान में, प्रतिवादी को विधिवत भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था।

याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान चुनाव याचिका में चुनाव को दो आधारों पर चुनौती दी, अर्थात् (i) चुनाव की गलत स्वीकृति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 18 (1) (सी) के तहत लौटने वाले उम्मीदवार का नामांकन; और (2) चुनाव में अनुचित प्रभाव के अपराध का मिशन, अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) के तहत कांग्रेस (1) पार्टी द्वारा चुनाव में प्रतिवादी को वोट देने के लिए व्हिप जारी करके।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि इसमें काफी खामियां थीं

245 246

लौटने वाले उम्मीदवार के नामांकन पत्र जिन्हें जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 ई (3) (ई) के अनुसार अस्वीकार करने की आवश्यकता थी; कि लौटने वाले उम्मीदवार के प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता थाः

धारा 5 बी की उप-धारा (2), जैसा कि प्रमाण पत्र से पता चलता है कि लौटे उम्मीदवार को 94 पलाई की मतदाता सूची में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत किया गया था।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 'जो' ओट्टापलम (एससी) 'संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं था, जिसका उल्लेख नामांकन पत्र में किया गया था, लेकिन' मूवाट्टुपुड़ा 'संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में; और यह कि प्रमाण पत्र में निर्वाचक का' अभिभावक का नाम '' रमन 'के रूप में दिखाया गया था, जबकि निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित कॉलम का शीर्षक था 'पिता/माता/अभिभावक/पति का नाम'।

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि इससे संबंधित कोई परीक्षण योग्य मुद्दा नहीं है

अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) में निहित अनुचित प्रभाव के अपराध के होने का आधार उस उद्देश्य के लिए आवश्यक अभिवचनों के अभाव में उत्पन्न हुआ; कि चुनाव याचिका में आपत्ति के लिए अधिनियम की धारा 18 (1) (सी) के तहत आधार उठाने को जांच के समय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया था; कि ली गई आपत्ति केवल प्रस्तावकों और समर्थनकर्ताओं के गलत विवरण की थी, न कि

वापस लौटाया गया उम्मीदवार, नामांकन पत्रों में; और यह कि दोष, यदि कोई हो, उस आधार पर नामांकन पत्रों की अस्वीकृति की अनुमति देने के लिए एक महत्वपूर्ण चरित्र का नहीं था।

चुनाव याचिका खारिज करते हुए, यह अदालत

पकड़नाः 1.1 . राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 18 (1) (ए) स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आधार का गठन करने के लिए, सार

टियाल सामग्री इस प्रकार हैः (1) चुनाव में अनुचित प्रभाव के अपराध का कमीशन; और (2) वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा या वापस लौटे उम्मीदवार की सहमति से किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका कमीशन। इस प्रकार, चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध, जैसा कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX-A में निहित धारा 171-C में परिभाषित किया गया है, किया गया होना चाहिए और वह अपराध या तो स्वयं लौटे उम्मीदवार द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा लौटे उम्मीदवार की सहमति से किया गया होना चाहिए। जब तक धारा 18 (1) (ए) के तहत आधार बनाने के लिए इन दोनों तत्वों का अनुरोध और साबित नहीं किया जाता है, तब तक चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए इस आधार को नहीं बनाया जा सकता है। [254 - डी-ई-एफ]

1.2 . याचिका का एक खाली अवलोकन यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि कम से कम

:

247

धर्ती पाकड़ बनाम। के. आर. नारायणन

मैदान के दो आवश्यक अवयवों में से एक का चुनाव याचिका में भी अनुरोध नहीं किया गया है। क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा व्हिप जारी करना अनुचित प्रभाव के बराबर हो सकता है, वर्तमान मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इस मुद्दे पर एक विचारणीय मुद्दे को उठाने के लिए आवश्यक अभिवचनों का अभाव है। चुनाव याचिका में अभिवचनों में कमी घातक है और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) में निहित आधार गुण-दोष पर विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है। [254 - एफ; 255-डी-ई]

मिथलेश कुमार बनाम। श्री आर. वेंकटरमण और अन्य। , [1988] 1 एससीआर 525,

पर भरोसा किया।

1.3 . धारा में निहित आधार से संबंधित अभिवचन

18 (1) (क) इस मुद्दे पर विचारणीय मुद्दा उठाने के लिए कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा न करें; और इसलिए, चुनाव याचिका, जहां तक इसका संबंध है

धारा 18 (1) (ए) में निहित आधार को इस कारण से अस्वीकार किया जाना चाहिए।

अकेले। [255 - एच]

2.1 . उप-धारा (1) में वैध नामांकन की आवश्यकताएँ और

(2) धारा 5 बी के तहत निर्दिष्ट संख्या में प्रस्तावकों और समर्थनकर्ताओं द्वारा नामांकन, नामांकन के लिए उम्मीदवार की सहमति, मतदाता सूची में प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति जिसमें उम्मीदवार को पंजीकृत मतदाता दिखाया गया है, निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित प्रपत्र में पूरा किए गए नामांकन पत्र को निर्दिष्ट समय पर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना है। एक उम्मीदवार के रूप में पात्रता की शर्तों का स्थान और पूर्ति। इसके लिए उम्मीदवार की सही पहचान आवश्यक है। [261 - बी-सी]

2.2 . नामांकन में भरे जाने वाले विवरणों का उद्देश्य

धारा 5 बी की उप-धारा (1) और (2) के अनुसार

नियमों के नियम 4 और प्रपत्र 3 के साथ पढ़ा गया अधिनियम, उम्मीदवार की सही और स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए है, और यह इंगित करने के लिए है कि चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा किया गया है। वापसी अधिकारी को किसी भी विसंगतियों को सुधारने की अनुमति देने की भी आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी अस्पष्टता या गलत विवरण को दूर किया जा सके। [260 - जी]

2.3 . जब तक कि नामांकन पत्र में दोष या कमी न हो

इसमें एक महत्वपूर्ण चरित्र है, धारा 5 ई (5) निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करने का आदेश देती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि नामांकन पत्र में कोई गलती या दोष है जो केवल

उम्मीदवार का गलत विवरण है, लेकिन गलत विवरण ऐसा है कि यह किसी को भी गुमराह नहीं करता है और उम्मीदवार की पहचान पर कोई संदेह नहीं है।

निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र की जांच करने के अपने कर्तव्य का पालन करने में सक्षम बनाना ताकि यह पता लगाया जा सके कि उम्मीदवार को वैध रूप से नामित किया गया है या नहीं। फिर गलती, यदि कोई हो, एक महत्वपूर्ण चरित्र की नहीं है। [260 - एच; 261-ए]

2.4 . वर्तमान मामले में एक दूरस्थ सुझाव भी नहीं है कि

अपनी उम्मीदवारी के लिए दायर नामांकन पत्रों द्वारा नामित उम्मीदवार के रूप में प्रत्यर्थी की पहचान करने में कोई कठिनाई या संदेह था, क्योंकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का वर्णन करने में कोई गलती हुई थी।

'94 पलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' का जवाब देते हुए जिसमें प्रतिवादी

निर्वाचक के रूप में पंजीकृत था या अपने पिता 'रमन' का नाम 'संरक्षक का नाम' के बजाय 'संरक्षक का नाम' के रूप में लिखे कॉलम के नीचे दिखा रहा था पिता/माता/संरक्षक/पति। यहां तक कि याचिकाकर्ता को भी इन दोषों से गुमराह नहीं किया गया था, और यही कारण है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के नामांकन पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, भले ही

याचिकाकर्ता ने जांच के समय अन्य कारणों से आपत्ति जताई थी।

[261 - डी-ई]

2.5 . धारा 5 ख (2) की अपेक्षा है-कि संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति

जिसमें उम्मीदवार 'निर्वाचक' के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक के साथ होगा। नामांकन पत्र। प्रमाणपत्र की सामग्री, इसलिए प्रत्येक के साथ संलग्न

नामांकन पत्र, एक प्रमाणित प्रति की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करता है

विधानसभा के लिए मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि निर्वाचन क्षेत्र जिसमें प्रतिवादी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत था। द.

प्रमाणपत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और नामांकन का नाम नहीं है राष्ट्र पत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख ओट्टापलम (एससी) के रूप में किया गया है।

मूवाट्टुपुड़ा के बजाय। [257 - जी-एच; 258-ए]

2.6 . संसदीय दल के लिए कोई अलग मतदाता सूची नहीं है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थिति और मतदाता सूची में शामिल हैं -

सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची

संसदीय क्षेत्र। [258 - एफ]

2.7 . संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वर्णन में विसंगति

'94 पलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' के अनुरूप जिसमें जवाब

स्तम्भ जिसके तहत प्रत्यर्थी के पिता का नाम लिखा जाता है, नहीं हैं पर्याप्त प्रकृति के दोष जिनके लिए नामांकन की अस्वीकृति की आवश्यकता होती है

अधिनियम की धारा 5 ई (3) (ई) में निहित आधार पर। [259 - डी]

2.8 . संसदीय दल के सदस्य के नाम का उल्लेख करने में गलती बनाम।

के. आर. नारायणन [वर्मा, जे.]

249

विधानसभा में मूवाट्टुपुड़ा के बजाय ओट्टापलम (एससी) के रूप में स्थिति

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें प्रत्यर्थी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत था

'94 पलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' के रूप में सही ढंग से वर्णित किया गया था

जिसने किसी को गुमराह नहीं किया, यहां तक कि याचिकाकर्ता को भी नहीं, और यह था,

इसलिए, यह सारवान प्रकृति का दोष नहीं है। इसलिए, यह नहीं हो सकता है

के अनुसार नामांकन पत्र की अस्वीकृति की अनुमति देने के लिए आधार अधिनियम की धारा 5 ई (3) (ई)। [261 - एफ; 262-डी]

करनैल सिंह बनाम। चुनाव न्यायाधिकरण, हिसार और अन्य, 10 ईएलआर 189

(एससी); राम अवधेश सिंह बनाम। सुमित्रादेवी और अन्य। , [1972] 2 एससीआर 674 और

डेविस बनाम। एल्स्बी ब्रदर्स लिमिटेड, [1960] 3 पी. पर सभी ई. आर. 672। 676 , संदर्भित किया गया।

मौलिक न्यायनिर्णयः 1992 की चुनाव याचिका संख्या 3।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 और भाग III के तहत

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम सं। 1952 का XXXI।)

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

एम. के. बनर्जी, महान्यायवादी, ए. के. गांगुली, सोली जे. सोराबजी,

उत्तरदाताओं के लिए पी. एच. पारेख, आर. एफ. नरीमन, उदय यू. ललित, एस. गजल, सुश्री मधुर खाती, सुश्री ए. सुभाशिनी और अनिल श्रीवास्तव।

निर्वाचन अधिकारी के लिए जी. रामास्वामी और सुश्री बीनू टम्टा।

निर्वाचन आयोग के लिए एस. मुरलीधर। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वर्मा, जे. यह चुनाव याचिका चुनाव पर सवाल उठाती है

श्री के. आर. नारायणन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.7.1992 की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 31.7.1992 को

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। याचिकाकर्ता काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पाकड़ और

प्रतिवादी श्री के. आर. नारायणन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और 1.8.1992 पर आयोजित जांच में, दोनों के नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध पाए गए। याचिकाकर्ता ने जांच के समय प्रतिवादी द्वारा दायर नामांकन पत्रों की वैधता पर आपत्ति जताई, लेकिन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। इन दो व्यक्तियों को ही वैध रूप से नामित उम्मीदवार घोषित किया गया था। और मतदान 19.8.1992 पर आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी, श्री के. आर. नारायण, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1993] एसयूपीपी थे।

250

भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित। 17.9.1992 पर, यह चुनाव याचिका चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी जाती है

दो आधारों पर, अर्थात् (i) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 (जिसे 'अधिनियम' कहा जाता है) की धारा 18 (1) (सी) के तहत वापस लौटे उम्मीदवार के नामांकन की गलत स्वीकृति; और (ii)

कांग्रेस (1) पार्टी द्वारा व्हिप जारी करके अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) के तहत चुनाव में अनुचित प्रभाव के अपराध का एक आधार चुनाव में उत्तरदाता को वोट देना। वर्तमान चुनाव याचिका के प्रयोजन के लिए धारा 18 का सामग्री भाग निम्नानुसार है:

" 18. (1) यदि उच्चतम न्यायालय की राय है, -

(क) कि चुनाव में रिश्वत या अनुचित प्रभाव का अपराध

लौट आए उम्मीदवार द्वारा या किसी द्वारा किया गया है वापस लौटे उम्मीदवार की सहमति के साथ व्यक्ति; या

XXX

XXX

XXX

(ग) कि किसी भी उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से किया गया है।

सफल उम्मीदवार का नामांकन या नामांकन किया गया है

गलत तरीके से स्वीकार किया गया;

सर्वोच्च न्यायालय लौटने वालों के चुनाव की घोषणा करेगा

उम्मीदवार को शून्य होना चाहिए।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, रिश्वत के अपराध और

चुनाव में अनुचित प्रभाव का वही अर्थ होता है जिसमें

भारतीय दंड संहिता का अध्याय IX-A "।

उपरोक्त दो आधारों के लिए प्रासंगिक तथ्य जिनके आधार पर चुनाव

यह याचिका दायर की गई है अब कहा गया है। की योग्यता एक उम्मीदवार के रूप में इस चुनाव याचिका को दायर करने के लिए याचिकाकर्ता विवाद में नहीं है। केवल एक ही सवाल हैः जिन आधारों पर चुनाव याचिका दायर की गई है, क्या दोनों या कोई आधार बनाए गए हैं?

गलत स्वीकृति की धारा 18 (1) (सी) में आधार का समर्थन करना

प्रत्यर्थी के वापस लौटे उम्मीदवार के नामांकन में, याचिकाकर्ता का आरोप है कि वापस लौटे उम्मीदवार के सभी नामांकन पत्रों में पर्याप्त दोष था, जिसके लिए 251 के अनुसार उनकी अस्वीकृति की आवश्यकता थी।

धर्म पाक-1. के. आर. नारायणन (वर्मा, जे.)

जाँच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 ई (3) (सी)। यह आरोप लगाया जाता है कि धारा 5 बी की उप-धारा (1) और (2) की आवश्यकता का पालन करने में विफलता हुई, क्योंकि लौटे उम्मीदवार के नामांकन पत्र निर्धारित फॉर्म में पूरे नहीं किए गए थे, और किसी भी नामांकन पत्र के साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति नहीं थी, जिसमें उम्मीदवार 'मतदाता के रूप में पंजीकृत है'। इन प्रावधानों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, '1974 (जिसे नियम कहा जाता है) के नियम 4 और फॉर्म 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र का रूप निर्धारित किया गया है। प्रपत्र 3 में निर्वाचक सूची में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम उल्लेख करना आवश्यक है जिसके लिए उम्मीदवार निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। प्रत्यर्थी के नामांकन पत्रों में, मतदाता सूची में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिए लौटे उम्मीदवार को मतदाता के रूप में पंजीकृत दिखाया गया है, 'ओट्टापलम (एससी)' के रूप में उल्लिखित है। प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ, धारा 5 बी की उप-धारा (2) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है, जो इस प्रकार हैः

" प्रमाण पत्र *

प्रमाणित किया कि श्री के. आर. नारायणन का नाम, कोचेरिल

घर, वार्ड नं. आठवीं उझावूर पंचायत, मीनाचिल तालुक,

केरल राज्य के कोट्टायम जिले को मतदाता सूची 1989 में शामिल किया गया है।

94 पलाई विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या 101। असली सार

जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः

मतदाता का नाम

एस. एल. नहीं। मकान नं.

घर का नाम

(कोचेरिल)

के आर नारायणन

192

61

का नाम

उम्र के हिसाब से

सेक्स

संरक्षक

1.1.1989

68

रमन

पुरुष।

श्री के. आर. नारायणन की आयु 1.1.1992 के अनुसार 71 (सत्तर) है।

एक)। आगे प्रमाणित किया गया कि मतदाता सूची 1989 जिसमें से उद्धरण है

ऊपर उद्धृत नवीनतम और वर्तमान सूची है।

तालुक कार्यालय।

एसडी

/

मीनाचिल।

निर्वाचक पंजीकरण

अधिकारी और

तहसीलदार

तारीखः 29.7.1992

मीनाचिल "।

जे.

याचिकाकर्ता का तर्क है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न है

ए.

वापस लौटे उम्मीदवार का प्रत्येक नामांकन पत्र संतुष्ट नहीं करता है धारा 5 ख की उप-धारा (2) की आवश्यकता, क्योंकि यह एक

मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति ';

और इस प्रमाण पत्र से पता चलता है कि लौटे उम्मीदवार को एक के रूप में पंजीकृत किया गया था

94 पलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में निर्वाचक जो है

बी.

में उल्लिखित 'ओट्टापलम (एससी)' संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं नामांकन पत्र लेकिन 'मूवाट्टुपुड़ा' संसदीय क्षेत्र में। द.

निर्वाचक के संरक्षक को 'रमन' के रूप में जबकि निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कॉलम का शीर्षक 'पिता/माता/ग्वार का नाम' है।

सी डियान/पति '। याचिकाकर्ता के अनुसार, इन दोषों को अमान्य कर दिया गया

प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी के लिए दाखिल किए गए सभी नामांकन पत्र, और

: : टी.

इसलिए, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी।

चुनाव याचिका में चुनौती देने के लिए दूसरा आधार लिया गया।

चुनाव, अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) के तहत 'अनुचित प्रभाव' का है। नज़र में

डी.

वापस लौटे उम्मीदवार की ओर से एक मजबूत आपत्ति है कि कोई नहीं है

इस आधार के संबंध में, जिस पर याचिकाकर्ता ने इस उद्देश्य के लिए भरोसा किया है। आधार से संबंधित चुनाव याचिका में एकमात्र अभिवचन धारा है

अधिनियम का ई 18 (1) (ए) पैरा 10,11 में है और आधार (1) और (III) पैरा 14 में है।

जिनका विवरण इस प्रकार हैः -.....

में से

" 10. कि निर्वाचन अधिकारी ने लिखित आपत्तियों पर कोई आदेश पारित किए बिना, असंवैधानिक रूप से, भविष्य में दबाव या लाभ की अनुचित उम्मीद में प्रतिवादी के नामांकन पत्र को अवैध रूप से स्वीकार कर लिया।

एफ.

11. कि सत्ता में सत्तारूढ़ दल, जो भविष्य को बदलने के लिए सक्षम है, ने लौटे उम्मीदवार के पक्ष में व्हिप जारी किया, चुनाव को प्रभावित करने वाला प्रतिवादी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है

जी.

यह। चाबुक की एक प्रति संलग्न की गई है और इसे अनुलग्नक 'डी' के रूप में चिह्नित किया गया है।

:

XXX

XXX

" 14. कि याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय में जा रहा है

दूसरों के बीच।

एच.

7 धर्ती पाकड़ बनाम। के. आर. नारायणन [वर्मा, जे.]

253

मैदान

1 . कि व्हिप अनुलग्नक 'डी' अनुच्छेद 66 का उल्लंघन है

संक्रमणरोधी अधिनियम को देखते हुए भारत का संविधान

बी. जे. पी. के 5 एम. पी. के प्रस्तावक अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे थे।

चुनाव की अवधि के दौरान इसलिए सभी राजनीतिक दल

और उनके नेताओं ने चुनाव का मजाक उड़ाया

भारत के उपराष्ट्रपति ने वापस लौटे उम्मीदवार का प्रस्ताव रखा अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में श्री के. आर. नारायणन

उम्मीदवार जो संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है इसलिए यह भारत के अनुच्छेद 14,21 और 38 का उल्लंघन है।

भारत का संविधान।

X

XX

XXX

XXX

III. कि सभी प्रकार के अनुचित प्रभाव चाबुक के माध्यम से

80 के रूप में चुनाव में भ्रष्ट प्रथाओं के बराबर प्रस्तावक भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 का उल्लंघन करते हैं

संक्रमण-रोधी अधिनियम का दृष्टिकोण "।

जवाब में विद्वान वकील श्री सोली जे. सोराबजी ने तर्क दिया

अधिनियम की धारा 18 (1) (सी) के तहत जांच के समय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी आपत्ति नहीं उठाई गई थी। केवल प्रस्तावकों और समर्थनकर्ताओं का गलत विवरण, न कि वापस किए गए का

उम्मीदवार, नामांकन पत्रों में। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अब उठाया गया आधार एक स्पष्ट विचार के बाद है और इसका कोई परिणाम नहीं है क्योंकि नामांकन पत्रों में दिए गए विवरण से लौटे उम्मीदवार की

पहचान में कभी कोई अस्पष्टता नहीं थी, नामांकन पत्र में आवश्यक विवरणों का एकमात्र उद्देश्य उम्मीदवार की स्पष्ट रूप से पहचान करना और चुनाव के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करना था। यह भी 254 था।

प्रस्तुत किया कि यदि इस तरह की आपत्ति, जांच के समय उठाई जाती है, तो नामांकन पत्रों में तकनीकी दोष को सुधारने में सक्षम होता।

यह हमारे सामने आम आधार था कि चुनाव याचिका में कोई सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसे स्वीकार करने पर निर्णय लिया जा सकता था। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्य और दस्तावेज, जिनकी सामग्री को स्वीकार किया गया था। इसलिए दोनों पक्षों की दलीलें उसी आधार पर सुनी गईं।

अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) में निहित 'अनुचित प्रभाव' के आधार पर पहले विचार किया जाता है। उपरोक्त उद्धृत प्रावधान के अनुसार

स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जमीन का गठन करने के लिए, आवश्यक सामग्री हैंः (1) चुनाव में अनुचित प्रभाव के अपराध का कमीशन; और (2) वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा या वापस लौटे उम्मीदवार की सहमति से किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका कमीशन। इस प्रकार चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध, जैसा कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX-A में निहित धारा 171-C में परिभाषित किया गया है, किया गया होना चाहिए और वह अपराध या तो स्वयं लौटे उम्मीदवार द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा लौटे उम्मीदवार की सहमति से किया गया होना चाहिए। जब तक धारा 18 (1) (ए) के तहत आधार बनाने के लिए इन दोनों तत्वों का अनुरोध और साबित नहीं किया जाता है, तब तक चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए इस आधार को नहीं बनाया जा सकता है। चुनाव याचिका में इस आधार से संबंधित पूरी दलील ऊपर उद्धृत की गई है। उसी का एक स्पष्ट प्रमाण यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि चुनाव याचिका में जमीन के दो आवश्यक अवयवों में से कम से कम एक का अनुरोध भी नहीं किया गया है।

निर्वाचन याचिका में कहीं भी ऐसा कोई कथन नहीं है कि कांग्रेस (1) पार्टी द्वारा व्हिप जारी करके कथित रूप से अनुचित प्रभाव का अपराध या तो उम्मीदवार द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा लौटे उम्मीदवार की सहमति से किया गया था। वहाँ

यह एक फुसफुसाहट या आकस्मिक दावा भी नहीं है कि लौटा हुआ उम्मीदवार कांग्रेस (1) पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों को व्हिप जारी करने में किसी भी तरह से जुड़ा हुआ, शामिल या सहायक था, 255

धर्ती पाकड़ बनाम। के. आर. नारायणन (वर्मा, जे.)

चुनाव में। कांग्रेस (1) पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा जारी दिनांकित 14.8.1992 (चुनाव याचिका के लिए अनुलग्नक-D) पत्र में भी व्हिप जारी करने में लौटे उम्मीदवार की किसी भी भूमिका का उल्लेख नहीं है।

लौटने वाले उम्मीदवार के. आर. नारायणन को 'एक सर्वसम्मत उम्मीदवार' के रूप में वर्णित करते हुए, जाहिर है कि वह कई राजनीतिक दलों की सहमति से चुने गए उम्मीदवार थे। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि उनके जवाबी हलफनामे में जवाब में कमी आई है, यहां तक कि चुनाव याचिका में इस तरह की किसी भी दलील के बिना, स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया गया है कि कांग्रेस (1) पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को व्हिप जारी करने में उनकी कोई भूमिका थी। इस इनकार का कोई जवाब नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कोई अन्य उम्मीदवार स्थापित नहीं किया गया था और प्रतिवादी को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था, जो राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से चुना गया उम्मीदवार था। याचिकाकर्ता, जो एकमात्र अन्य उम्मीदवार थे, उन्हें केवल एक वोट मिला, जैसा कि उन्होंने सुनवाई में कहा था।

सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में भी व्हिप जारी किया जाता है

किसी राजनीतिक दल द्वारा अनुचित प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है

वर्तमान मामले में निर्णय, इस मुद्दे पर एक परीक्षण योग्य मुद्दा उठाने के लिए आवश्यक अभिवचनों के अभाव के कारण।

मिथलेश कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय के हाल के संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करना पर्याप्त है। श्री आर. वेंकटरमण और अन्य। , [1988] 1 एस. सी. आर. 525, यह इंगित करने के लिए कि चुनाव याचिका में अभिवचनों में ऐसी कमी घातक है और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) में निहित आधार गुण-दोष पर विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह की स्थिति में जहां अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) में निहित अनुचित प्रभाव का आधार इस तथ्य के कारण उठाया गया था कि कांग्रेस (1) पार्टी द्वारा एक व्हिप जारी किया गया था, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं था कि अनुचित प्रभाव के बराबर कोई भी कार्य स्वयं लौटे उम्मीदवार द्वारा किया गया था। या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी सहमति से, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह जांच करना अनावश्यक था कि क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा इस तरह का व्हिप जारी करना चुनाव को दूषित करने वाले अनुचित प्रभाव के बराबर है। इस पहलू पर, इस न्यायालय के पहले के फैसलों के संदर्भ में, उसमें विस्तार से विचार किया गया था और इसलिए, यहां इसे दोहराना अनावश्यक है। उस निर्णय के बाद, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा 18 (1) (ए) में निहित आधार से संबंधित अभिवचन इस बिंदु पर एक परीक्षण योग्य मुद्दा उठाने के लिए कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करते हैं और इसलिए, चुनाव याचिका, जहां तक वह धारा 18 (1) (ए) में निहित आधार से संबंधित है, केवल इसी कारण से खारिज की जानी चाहिए।

" अब विचार के लिए केवल एक ही प्रश्न शेष है, वह हैः चाहे वह

लौटने वाले उम्मीदवार को गलत तरीके से स्वीकार किया गया था

और अधिनियम की धारा 18 (1) (सी) के तहत चुनाव को अलग करने के लिए? इस आधार के लिए प्रासंगिक अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

" 5 बी. (1) के खंड (ओं) के तहत नियुक्त तिथि को या उससे पहले

धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार या तो व्यक्तिगत रूप से

या उसके किसी भी प्रस्तावक या समर्थनकर्ता द्वारा, के घंटों के बीच

दोपहर के ग्यारह बजे और दोपहर के तीन बजे,

इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर निर्वाचन अधिकारी को सौंपें धारा 5 के तहत जारी सार्वजनिक सूचना में एक नामांकन पत्र

निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया और उम्मीदवार द्वारा सदस्यता ली गई नामांकन के लिए सहमति के रूप में, और

(क) राष्ट्रपति चुनाव के मामले में भी कम से कम दस निर्वाचकों द्वारा

प्रस्तावक के रूप में और कम से कम दस निर्वाचक अनुमोदक के रूप मेंः

(ख) उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में भी कम से कम पाँच बार

प्रस्तावक के रूप में निर्वाचक और समर्थनकर्ता के रूप में कम से कम पाँच निर्वाचकः

बशर्ते कि कोई नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा

निर्वाचन अधिकारी उस दिन जो सार्वजनिक अवकाश होता है।

(2) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ एक प्रमाण पत्र होगा।

मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रति

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें उम्मीदवार पंजीकृत है

निर्वाचक के रूप में।

XXX

XXX

XXX

5 ई. (1)

XXX

XXX

(3) इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन की जांच करेगा।

कागजात और उन सभी आपत्तियों का निर्णय करेगा जो किसी के लिए की जा सकती हैं

नामांकन पत्र और या तो इस तरह की आपत्ति पर या अपने दम पर

प्रस्ताव, ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझता है, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार कर देंः

(अ)

257

धर्ती पाकड़ बनाम। के. आर. नारायणन [वर्मा, जे.]

XXX

XXX

XXX

(ई) कि किसी का भी पालन करने में विफलता हुई है

धारा 5 ख या धारा 5 ग के प्रावधान।

XXX

XXX

XXX

(5) निर्वाचन अधिकारी किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा।

किसी भी दोष के आधार पर जो एक महत्वपूर्ण चरित्र का नहीं है।

XXX

XXX

XXX

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति

धारा 16 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 "।

वापस लौटे उम्मीदवार के नामांकन पत्र में दोष, पर

यह आधार किस पर आधारित है, इसका संकेत पहले ही दिया जा चुका है। दोनों पक्षों द्वारा दायर हलफनामों के आधार पर निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रतिवादी, रमन के पुत्र के. आर. नारायणन को '94 पलाई विधानसभा क्षेत्र' की मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो मूवाट्टुपुड़ा संसदीय क्षेत्र के भीतर आता है, न कि ओट्टापलम (एससी) संसदीय क्षेत्र में। निर्वाचन पंजीयक कार्यालय और तहसीलदार, मीनाचिल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में निर्वाचक के रूप में प्रत्यर्थी के विवरण में कोई अशुद्धि या दोष नहीं है, जिसे नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया गया था जब इसे दाखिल किया गया था। प्रमाणपत्र में

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी का नाम '94 पलाई विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या 101' की मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इसमें आगे 1989 की उस मतदाता सूची का 'सही उद्धरण' है और इसे नवीनतम और वर्तमान मतदाता सूची से उद्धरण के रूप में प्रमाणित करता है।

धारा 5 ख (2) की अपेक्षा है कि 'संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक सूची में उम्मीदवार जिसमें उम्मीदवार निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ होगा। प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ इस प्रकार संलग्न प्रमाण पत्र की सामग्री, उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 'मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति' की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करती है जिसमें प्रतिवादी एक मतदाता के रूप में पंजीकृत था। द 258

प्रमाणपत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम नहीं है और नामांकन पत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख मूवाट्टुपुड़ा के बजाय ओट्टापलम (एससी) के रूप में किया गया है। सवाल यह हैः क्या यह अंतर नामांकन पत्र की अस्वीकृति के लिए एक महत्वपूर्ण चरित्र का है?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 डी आंशिक रूप से है।

आई. आई. बी. 'संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक सूची' से संबंधित है और धारा 15 'विधानसभा के लिए निर्वाचक सूची' से संबंधित भाग III में है। निर्वाचन क्षेत्र, जो निम्नानुसार हैंः

" 13 डी. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची। - (1) द.

प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची, एक के अलावा

जम्मू और कश्मीर राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या

किसी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधान सभा नहीं है,

इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची शामिल है। उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर शामिल; और यह नहीं होगा

निर्वाचक नामावली को अलग से तैयार या संशोधित करना आवश्यक होगा

ऐसा कोई भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रः

XXX

XXX

XXX

15. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची। - प्रत्येक संविधान के लिए

यदि एक निर्वाचक नामावली होगी जिसे इसमें तैयार किया जाएगा

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग का निर्देशन और नियंत्रण "।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि कोई अलग चुनाव नहीं है

एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए तोरल सूची और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में सभी विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची होती है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र। इस प्रकार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें से '94 पलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र'

एक भाग वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसमें उत्तरदाता को एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया था और उसका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पाया जाना था जिसमें वह पंजीकृत था। वर्तमान मामले में प्रतिवादी को '94 पलाई विधानसभा क्षेत्र' की मतदाता सूची में एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत किया गया था, जैसा कि प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक निर्वाचक के रूप में प्रत्यर्थी के विवरण में कोई अस्पष्टता नहीं थी

आई।

नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र को पढ़ना। हालाँकि, गलती संबंधित पैरा 259 के नाम का उल्लेख करने में थी।

धर्ती पाकड़ 1. के. आर. नारायणन (वर्मा, जे.)

94 पलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए दायित्व निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिवादी के नामांकन पत्र में 'मुवाट्टुपुआज़' के बजाय 'ओट्टापलम (एससी)' के रूप में लिखा गया है। इस गलती ने किसी को गुमराह नहीं किया, यहां तक कि याचिकाकर्ता को भी नहीं, जो है

इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस तरह की आपत्ति याचिकाकर्ता द्वारा भी जांच के समय नहीं ली गई थी, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में प्रतिवादी के सही विवरण के बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं था। दूसरी गलती यह है कि प्रतिवादी के पिता 'रमन' का नाम 'अभिभावक का नाम' कॉलम के तहत लिखा गया है, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार उस कॉलम का शीर्षक 'पिता/माता/अभिभावक/पति का नाम' होना चाहिए था। हमारी राय में, इसे शायद ही एक दोष कहा जा सकता है, क्योंकि चूक, यदि कोई हो, तो उस कॉलम का पूरा शीर्षक देने में है और इसके तहत प्रतिवादी के पिता के नाम का उल्लेख करने में नहीं है।

अंतिम सवाल यह हैः क्या वर्णन करने में यह विसंगति है

94 पलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुरूप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें प्रत्यर्थी को निर्वाचक के रूप में पंजीकृत किया गया था, और स्तंभ के शीर्षक में कमी जिसके तहत प्रत्यर्थी के पिता का नाम लिखा गया है, पर्याप्त प्रकृति के दोष हैं जिनके लिए अधिनियम की धारा 5 ई (3) (ई) में आधार पर नामांकन की अस्वीकृति की आवश्यकता होती है? हम ऐसा नहीं सोचते हैं।

करनैल सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय। चुनाव न्यायाधिकरण, हिसार और अन्य, 10 ई. एल. आर. 189 (एस. सी.) ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि नामांकन की अस्वीकृति केवल एक तकनीकी दोष के लिए अनुमेय नहीं है, जिसका लगातार पालन किया गया है। उस मामले में, नामांकन पत्र में मतदाता सूची के उस हिस्से का नाम दर्ज नहीं किया गया था जिसमें उम्मीदवार का नाम था, लेकिन उम्मीदवार की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं थी। चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस आधार पर नामांकन पत्र की अस्वीकृति अनुचित थी। इस न्यायालय ने चुनाव न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की पुष्टि की और इस प्रकार निर्णय दियाः

" ..... एकमात्र दोष इंगित किया गया था कि नाम का

उसमें उप-विभाजन नहीं बताया गया था, लेकिन साक्ष्य पर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उम्मीदवार की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं थी और

उम्मीदवार ने स्वयं निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूची में अपने नाम की प्रविष्टि की ओर इशारा किया। इन परिस्थितियों में दोष एक तकनीकी था और न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से सही था कि दोष एक महत्वपूर्ण चरित्र 260 का नहीं था।

और कि नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

राम अवधेश सिंह बनाम में निर्णय का उल्लेख करना पर्याप्त है।

सुमित्रादेवी और अन्य। , [1972] 2 एस. सी. आर. 674, जिसमें कमाल सिंह से शुरू होने वाले इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया गया है, जो उद्देश्य या इस तरह के एक

प्रावधान और एक महत्वपूर्ण दोष की प्रकृति जो अस्वीकार करने की अनुमति देती है नामांकन पत्र। वहाँ लिया गया आधार लौटने वाले उम्मीदवार के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति का था, क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसमें लौटने वाले उम्मीदवार को एक उम्मीदवार के रूप में पंजीकृत किया गया था।

नामांकन पत्र में मतदाता का गलत उल्लेख किया गया था। इससे पहले इस न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित किया गया था, और यह माना गया था कि एक गलत विवरण

नामांकन पत्र में उम्मीदवार या प्रस्तावक की क्लेक्टरल रोल संख्या के बारे में नामांकन पत्र में एक भौतिक दोष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करते समय उसमें किसी भी गलत धारणा को सुधारने की अनुमति दे सकता है, जो इंगित करता है कि नामांकन पत्र भरने में हर गलती को सारवान प्रकृति का नहीं माना जाना चाहिए। हमारी राय में, धारा 5 ई की उप-धारा (5), जो निर्वाचन अधिकारी को रोकती है और किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देती है।

जो एक महत्वपूर्ण प्रकृति का नहीं है, स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान करता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित आधार पर वर्तमान मामले में प्रतिवादी के किसी भी नामांकन पत्र की अस्वीकृति नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति और अधिनियम की धारा 5 ई (5) का उल्लंघन होगी। अतः यह तर्क देना गलत है कि प्रत्यर्थी के नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से स्वीकार किए गए थे।

नामांकन पत्रों में गलती या दोष की प्रकृति

उत्तरदाता, जिसे एक अलग कोण से देखा जाता है, भी उसी संलयन की ओर ले जाता है। नियमों के नियम 4 और प्रपत्र 3 के साथ पठित अधिनियम की उप-धारा (1) और (2) धारा 5 बी के अनुसार नामांकन पत्र में दाखिल किए जाने वाले विवरणों का उद्देश्य उम्मीदवार की सही और स्पष्ट रूप से पहचान करना और यह इंगित करना है कि चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा किया गया है। किसी भी अस्पष्टता या गलत विवरण को दूर करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को किसी भी विसंगति में सुधार की अनुमति देने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब तक नामांकन पत्र में दोष या उसमें कमी महत्वपूर्ण नहीं है, तब तक धारा 5 ई (5) निर्वाचन अधिकारी को नामांकन को अस्वीकार नहीं करने का आदेश देती है।

कागज। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि नामांकन पत्र में कोई गलती या दोष है जो केवल उम्मीदवार का गलत वर्णन है, लेकिन

गलत वर्णन ऐसा है कि यह किसी को गुमराह नहीं करता है, और 261 की पहचान

धर्ती पाकड़ 1. के. आर. नारायणन (वर्मा, जे.)

उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी को अपना कार्य करने में सक्षम बनाने में कोई संदेह नहीं है।

नामांकन पत्र की जांच करने का कर्तव्य यह पता लगाने के लिए कि क्या उम्मीदवार

वैध रूप से नामित किया गया है, तो गलती, यदि कोई हो, तो महत्वपूर्ण नहीं है

चरित्र।

उप-धारा (1) और (2) में वैध नामांकन की आवश्यकताएँ

धारा 5 बी इस प्रकार हैः निर्दिष्ट संख्या में प्रस्तावकों द्वारा नामांकन और

अनुमोदनकर्ता, नामांकन के लिए उम्मीदवार की सहमति, की एक प्रमाणित प्रति

मतदाता सूची में प्रविष्टि जिसमें उम्मीदवार को पंजीकृत दिखाया गया है निर्वाचक, निर्धारित में पूरा किए गए नामांकन पत्र की प्रस्तुति

निर्दिष्ट समय के भीतर निर्दिष्ट स्थान पर निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र, और एक उम्मीदवार के रूप में पात्रता की शर्तों को पूरा करना। इसके लिए

उद्देश्य, उम्मीदवार की सही पहचान आवश्यक है। वहाँ नहीं है। यहां तक कि वर्तमान मामले में एक दूरस्थ सुझाव कि कोई कठिनाई थी

या अपनी उम्मीदवारी के लिए दायर नामांकन पत्रों द्वारा नामित उम्मीदवार के रूप में प्रतिवादी की पहचान करने में संदेह, वर्णन में किसी भी गलती के कारण

'94 पलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' के अनुरूप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें प्रत्यर्थी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत था या अपने पिता 'रमन' का नाम 'पिता/माता/अभिभावक/पति के नाम' के बजाय 'संरक्षक के नाम' के रूप में लिखे कॉलम के नीचे दिखा रहा है। यहां तक कि याचिकाकर्ता को भी इन दोषों से गुमराह नहीं किया गया था, और यही कारण है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के नामांकन पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, भले ही याचिकाकर्ता ने अन्य कारणों से जांच के समय आपत्ति उठाई हो।

संसदीय संविधान के नाम का उल्लेख करने में गलती

मूवाट्टुपुड़ा के बजाय ओट्टापलम (एससी) के रूप में, जब विधानसभा की स्थिति जिसमें प्रतिवादी को एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत किया गया था, को सही ढंग से '94 पलाई विधानसभा क्षेत्र' के रूप में वर्णित किया गया था, तो यह एक गलत नाम था जिसने किसी को भी गुमराह नहीं किया, यहां तक कि याचिकाकर्ता को भी नहीं, और यह, वहाँ, महत्वपूर्ण प्रकृति का कोई दोष नहीं था। यह निर्धारित करने के लिए सही परीक्षण कि क्या एक गलत विवरण केवल एक गलत नाम है या सारवान विवरण का दोष है। प्रकृति का संकेत डेविस वी में दिया गया था। एल्स्बी ब्रदर्स लिमिटेड, [1960] 3 पी. पर सभी ई. आर. 672। 676 निम्नानुसारः

" ..... अंग्रेजी कानून में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रश्न नहीं है

दस्तावेज़ के लेखक का क्या इरादा या मतलब था, लेकिन क्या

दस्तावेज़ को पढ़ने वाला समझदार व्यक्ति इसका अर्थ समझ लेगा;

और यह वह परीक्षण है जिसे एक सामान्य नियम के रूप में लागू किया जाना चाहिए

गलत नाम के मामले जिनमें कई अन्य शामिल हो सकते हैं

एक रिट पर गलत नाम के अलावा स्थितियाँ, उदाहरण के लिए 262 के रूप में गलती

अनुबंध बनाने में पहचान के लिए। परीक्षण होना चाहिएः कैसे होगा? दस्तावेज़ प्राप्त करने वाला एक उचित व्यक्ति इसे लेता है? अगर, सभी में

मामले की परिस्थितियों और समग्र रूप से दस्तावेज़ को देखना

वह अपने आप से कहताः बेशक इसका मतलब मुझे होना चाहिए, लेकिन उनके पास है

मेरा नाम गलत है ", तो केवल गलत नाम का मामला है। अगर,

दूसरी ओर, वह कहेंगेः " मैं दस्तावेज़ से नहीं बता सकता।

चाहे वे मुझसे मतलब रखते हैं या नहीं और मुझे बनाना होगा

पूछताछ ", तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्षेत्र से परे जा रहा है गलत नाम "।

(जोर दिया गया)

इस तरह से भी देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि गलती हुई है

या प्रतिवादी के नामांकन पत्र में कोई दोष, यदि कोई हो, एक महत्वपूर्ण चरित्र का नहीं था और इसलिए, यह अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता था। अधिनियम की धारा 5 ई (3) (ई) के अनुसार नामांकन पत्र की अस्वीकृति। यदि जांच के समय किसी ने दोष की ओर इशारा किया होता,

निर्वाचन अधिकारी ने निश्चित रूप से और उचित रूप से इसके सुधार की अनुमति दी होगी, क्योंकि यह केवल एक तकनीकी दोष था। हालांकि, किसी को भी, यहां तक कि याचिकाकर्ता को भी ऐसा कोई संदेह नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी की पहचान और एक उम्मीदवार के रूप में उनकी पात्रता निर्विवाद थी। इस कारण से, इस आपत्ति को जांच के समय भी नहीं उठाया गया था, बल्कि केवल चुनाव याचिका में एक विचार के रूप में उठाया गया था।

तथ्य, हालांकि, यह है कि इस तकनीकी दोष में प्रवेश किया

अपने नामांकन पत्र दाखिल करने में कई राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों से लिए गए पुरुषों के समूह के जुड़ाव के बावजूद प्रतिवादी के नामांकन पत्र। चुनाव याचिका इस विसंगति को प्रकट करने के उद्देश्य को पूरा करती है जिसे पुरुषों की आकाशगंगा पूरी तरह से याद करती है। यह एक अलग बात है कि दोष केवल तकनीकी है और पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं है।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 18 (ए) (सी) में निहित आधार हैः

उत्तरदाता के चुनाव की वैधता को चुनौती देने के लिए भी उपलब्ध नहीं है

दाँत।

नतीजतन, चुनाव याचिका खारिज कर दी जाती है। नं. सी. सी. एस. टी. एस.

चुनाव याचिका खारिज कर दी गई।

वी. पी. आर